



अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की टाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण

पदेन संरक्षक

94133-89665

राकेश कुमार

प्रदेश अध्यक्ष

9414591735

सवाई नाथ सपेरा

कार्यकारी अध्यक्ष

7976166691

योगेश खींची

प्रदेश महासचिव

9664134883

लखन कुमार डाबोडिया

प्रदेश कोषाध्यक्ष

9772516094

10.12.2022

क्रमांक

1207
10
1997

श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश महोदय,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय,
नई दिल्ली।

दिनांक :

JUSTICE DELAYED, JUSTICE DENIED

विषय:- वंचित दलितों की सहायतार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से कीमिलेयर को बाहर करने बाबत।

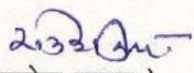
संदर्भ:- सिविल याचिका संख्या 02/2018 के शीघ्र निस्तारण हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजनाओं से अनुदान और आर्थिक सहायता पहुंचाने की व्यवस्थाएँ की हुई हैं। पिछले 70 वर्षों में सम्पूर्ण आरक्षण व्यवस्था और अरबों रुपये की सरकारी सहायता का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में केवल 4-5 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी उठाया जा रहा है। अजा/अजजा वर्ग के लगभग 95 प्रतिशत परिवार आज भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, पिछड़े हुये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लगातार चार संविधान पीठों द्वारा (एम.नागराज बनाम भारत सरकार, रोहिताश भोंखर बनाम भारत सरकार, जरनैल सिंह बनाम भारत सरकार एवं चैम्बरलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश) निर्णय दिया जा चुका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से कीमिलेयर को बाहर किया जाए ताकि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ सुपात्र दलितों और पिछड़ों तक पहुंच सके। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त संविधान पीठों के निर्णयों की पालना करने का साहस नहीं किया गया है।

समता आन्दोलन के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन सिविल याचिका संख्या 02/2018 दायर की हुई है जिसमें नोटिस जारी किये हुये हैं। एम. नागराज के प्रकरण में संविधान पीठ के दिये गये निर्णय के वर्ष 2006 से अब तक 16 वर्षों में लाखों की संख्या में सुपात्र दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभों को सम्पन्न अपात्र लोगों द्वारा लगातार हड़पा जा रहा है। आप श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी उपरोक्त याचिका संख्या 02/2018 को तत्काल निर्णित करवा कर सम्पन्न और अगड़े लोगों को अजा/अजजा वर्ग से बाहर करके पूरे देश और प्रदेशों के करोड़ों वंचित दलितों को न्याय दिलवाएँ। सादर।

भवदीय,


(राकेश कुमार)
अध्यक्ष

प्रति:-

सभी लोकसभा एवं राज्य सभा के सम्माननीय सांसदों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।